

## न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० मास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 90/2013 G.C.M.S. No. 2013/00100 दर्ज दिनांक : 23.12.2013  
अपीलार्थी:

1. सोहनलाल पुत्र देवाजी, उम्र 42 वर्ष, जाति भाट, निवासी बोगला, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

### बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर पाली।
2. भूमिधारी तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा सिविल मूल वाद संख्या 54/2011 बअनवान सोहनलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2012 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार—

1. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांत।
2. राजकीय पैरोकार रेस्पोंडेन्ट्स।

### निर्णय

दिनांक: 19.09.2025

अपीलान्त की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा सिविल मूल वाद संख्या 54/2011 बअनवान सोहनलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2012 के विरुद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांत द्वारा धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत एक वाद प्रस्तुत कर मौजा बोगला की राजस्व सीमा में पुराने खसरा नंबर 484 रकबा दो बीघा, खसरा नंबर 487 रकबा सवा चार बीघा चार बिस्वा, खसरा नंबर 481 रकबा एक बीघा व खसरा नंबर 333 रकबा डेढ बीघा दो बिस्वा किस्म बारानी दायम कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के संबंध में खातेदारी हक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा विधिविरुद्ध है। चूंकि संवत 2033 में दिनांक 10.07.1971 को उक्त भूमि वादी के पिता देवा पुत्र सवा जाति भाट निवासी बोगला को आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन की गई। उस समय उसकी उक्त भूमि की किस्म बारानी दायम की राजस्व कर्मचारी की गलती से रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया था तथा वादी के पिता के नाम खाते में दर्ज नहीं की गई। बाद में सेटलमेंट कर्मचारियों ने

*(Handwritten signature)*

उक्त भूमि सिवायचक से हटाकर गोचर दर्ज कर दी गई। जबकि सेटलमेंट कर्मचारियों को न तो किस्म परिवर्तन व इन्द्राज में परिवर्तन करने का अधिकार है। गोचर के उपयोग में आने से गोचर दर्ज का निर्णय में अंकन विधिसम्मत नहीं हैं। गोचर भूमि करने का अधिकार राजस्थान राज्य/जिला कलक्टर को होता है तथा अपीलांट के पिता को सुनवाई का अवसर दिए बिना वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तित कर दी गई। हस्तगत प्रकरण में तनकीयों का निर्णय पत्रावली व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किए बिना किया गया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व उसके अधिवक्ता को न तो निर्णय सुनाया व न अवगत कराया। अपीलांट सदैव कोर्ट आता तो फाईल साहब के पास होने का कहकर रीडर भेज देता। दिनांक 05.09.2013 को रीडर ने कहा कि साहब ने तुम्हारा दावा खारिज कर दिया है। तब सर्वप्रथम निर्णय का ज्ञान हुआ। उसके पूर्व कोई ज्ञान अपीलांट व उसके अधिवक्ता को नहीं था। अपीलांट ने उसी दिनांक 05.09.2013 को नकल आवेदन कर निर्णय की नकल ली तथा श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा रेस्पोंडेंट सरकार के विरुद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2012 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरुद्ध वादी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 01.11.2013 को लगभग 17 माह अर्थात् लगभग 510 दिवस के दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व उसके अधिवक्ता को फैसला नहीं सुनाया तथा न ही अवगत कराया। दिनांक 05.09.2013 को रीडर ने कहा कि साहब ने तुम्हारा दावा खारिज कर दिया है।

तब सर्वप्रथम निर्णय का ज्ञान हुआ। उसके पूर्व कोई ज्ञान अपीलांट व उसके अधिवक्ता

को नहीं था। अपीलांत ने उसी दिनांक 05.09.2013 को नकल आवेदन कर निर्णय की नकल ली तथा श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांत स्वयं वादी है तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया गया, जिनके द्वारा पैरवी की जाती रही। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका तथा अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांत के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र शर्मा तथा पैरोकार सरकार की प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर उनकी उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलांत द्वारा विलंब के कारण के रूप में दर्शित आधार भी युक्तियुक्त, सद्भाविक व स्वीकार योग्य नहीं होकर महज काल्पनिक व आधारहीन कारण है।
4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5- condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is preferred after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforesaid provision cannotes that the dismissal is mandatory



subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or referred to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमने माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में

*MAJ*

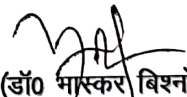
अविश्वसनीय रूप से 510 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरुद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि 510 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल माफी योग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

### आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दपतर हों।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
(डॉ० मास्कर बिश्नोई)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली